

अनियमति जमा योजनाओं पर प्रतर्बिंध लगाने संबंधी वधियक, 2018 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थायी वित्त समिति (Standing Committee on Finance-SCF) के गठन की सफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनियमति जमा योजनाओं पर प्रतर्बिंध लगाने संबंधी वधियक, 2018 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बट्टे

- 18 जुलाई, 2018 को अनियमति जमा योजनाओं पर प्रतर्बिंध लगाने संबंधी वधियक-2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे स्थायी वित्त समिति (Standing Committee on Finance-SCF) के सुपुर्द कर दिया गया था।
- 03 जनवरी, 2019 को इस वधियक की 17वीं रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया।
- इस संशोधन के पश्चात् यह वधियक देश में अवैध रूप से जमा राशियाँ जुटाने के जोखिम से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के ज़रिये गरीबों एवं भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मज़बूत हो जाएगा।
- इस संशोधित वधियक में प्रतर्बिंध लगाये जाने हेतु एक व्यापक अनुच्छेद लाया गया है, जिसके अंतर्गत जमा राशियाँ जुटाने वालों को किसी भी अनियमति जमा योजना का प्रचार-प्रसार, संचालन, वजिआपन जारी करने अथवा जमा राशियाँ जुटाने से प्रतर्बिंधित किया गया है।

वधियक के उद्देश्य

- यह वधियक अनियमति तौर पर जमा राशियाँ जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। इसके तहत ऐसी गतिविधियों को प्रत्याशति अपराध माना जाएगा, जबकि भौजूदा वधियाँ-सह-नियामकीय फ्रेमवर्क केवल व्यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या अप्रत्याशति रूप से प्रभावी होता है।
- वधियक में अपराधों के तीन प्रकार निर्दिष्ट किये गए हैं, जिनमें अनियमति जमा योजनाएँ चलाना, नियमति जमा योजनाओं में धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिफॉल्ट करना और अनियमति जमा योजनाओं के संबंध में गलत इरादे से प्रलोभन देना शामिल हैं।
- वधियक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, ताक लोगों की इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लग सके।
- वधियक में उन मामलों में जमा राशियों को वापस लौटाने या पुनर्भुगतान करने के पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं, जिनके तहत ये योजनाएँ किसी भी तरह से अवैध तौर पर जमा राशियाँ जुटाने में सफल हो जाती हैं।
- वधियक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों/परसंपत्तियों को ज़ब्त करने और जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान किये जाने के उद्देश्य से इन परसंपत्तियों को हासिल करने का प्रावधान किया गया है।

वधियक के प्रावधान

18 जुलाई, 2018 अनियमति जमा योजनाओं पर प्रतर्बिंध लगाने संबंधी वधियक-2018 को संसद में पेश किया गया जिसमें नमिनलखित व्यवस्था की गई है –

- अनियमति जमा राशियाँ जुटाने की गतिविधि पर पूर्ण प्रतर्बिंध।
- अनियमति जमा राशियाँ जुटाने वाली योजना का प्रचार-प्रसार अथवा संचालन के मामले में कठोर दंड।
- जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान के मामले में धोखाधड़ी और डिफॉल्ट करने पर कठोर दंड।
- जमा राशियाँ जुटाने वाले प्रतर्षिठान को डिफॉल्टर घोषित किये जाने की स्थिति में जमा राशियाँ पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकरण को अधिकृत करना।
- सक्षम प्राधिकरण को अधिकार सौंपना, जिसमें डिफॉल्टर प्रतर्षिठान की परसिम्पत्तियाँ ज़ब्त करने का अधिकार देना भी शामिल हैं।
- जमाकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान की निगरानी करने और अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई करने के लिये अदालतों को अधिकृत करना।
- वधियक में नियमति जमा योजनाओं की सूची पेश करना, इसमें एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके तहत केंद्र सरकार इस सूची को बड़ा या छोटा कर सकेगी।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2014 और मई 2018 के बीच की अवधि के दौरान अनधिकृत योजनाओं के 978 मामलों पर वभिन्न राज्यों/केंद्र-शासति प्रदेशों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level Coordination Committee-SLCC) की बैठकों में वधिार कथिा गया और उन्हें राज्यों के संबंघति नथिामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसथियों के सुपुर्द कथिा गया ।
- 2016-17 के दौरान इस तरह की योजनाओं से देश भर में बहुत से लोगों को आर्थकि नुकसान हुआ था जसिमें ज़यादातर गरीब और वत्तिथीय मामलों से अनभजिज़ लोग शामिल थे इस तरह की योजनाओं का जाल अनेक राज्यों में फैला हुआ है ।
- इसके बाद वत्ति मंत्री ने बजट भाषण 2017-18 में यह घोषणा की थी क्ति अवैध रूप से जमा राशजुटाने वाली योजनाओं पर अंकुश लगाने के लथि वधिथक के मसौदे को सार्वजनकि तौर पर पेश कथिा गया है और इसे अंतमि रूप देने के बाद जल्द ही संसद में पेश कथिा जाएगा ।

स्रोत - PIB

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/bill-for-restrictions-on-irregular-deposit-schemes-approves-proposal-of-official-amendment-in-2018>

